अध्याय

04

कीमतें और मुद्रास्फीतिः उतार-चढ़ाव को समझना

वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करते समय मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को समझना आवश्यक है। हालांकि आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में चरम पर थी, लेकिन नीतिगत उपायों की सहायता से इसमें गिरावट आई है। भारत में, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय पर किए गए हस्तक्षेपों के कारण वित्त वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति कम हुई। कोर मुद्रास्फीति एक दशक में अपने निम्नतम बिंदु पर पहुंच गई, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और मौसम की प्रतिकूल स्थितियों से प्रभावित हुई है।

प्याज और टमाटर की कीमतें उत्पादन में गिरावट से प्रभावित हुई हैं, जो आंशिक तौर पर यह प्रभाव मौसम की चरम स्थिति और मानसून से आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के कारण हैं। दलहन के मामले में, प्रमुख उत्पादक होने के बावजूद, भारत को मांग और आपूर्ति में अंतर का सामना करना पड़ता है। सरकार ने प्याज और टमाटर जैसी सब्जियों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत प्याज की खरीद करना और बफर स्टॉक भंडारण करना तथा प्याज व टमाटर की रियायती दर पर बिक्री शामिल है। साथ ही, दलहन की कीमतों संबंधी दबावों से निपटने के लिए कई प्रशासनिक उपाय किए गए हैं, जैसे कि रियायती दर पर खुदरा बिक्री, भंडारण सीमा और आयात को आसान बनाना।

अनुमान बताते हैं कि भारत की खुदरा मूल्य मुद्रास्फीति धीरे-धीरे लक्ष्य के अनुरूप हो जाएगी। वैश्विक पण्य (कमोडिटी) की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे संभावित रूप से कोर और खाद्य मुद्रास्फीति कम हो सकती है। कीमतों की निगरानी, जलवायु-प्रतिरोधी फसलों के विकास, फसल क्षति और कटाई के बाद होने वाली हानियों को कम करने के लिए मजबूत डेटा प्रणालियों द्वारा दीर्घकालिक कीमत स्थिरता प्राप्त की जा सकती है।

परिचय

4.1 वैश्विक अर्थव्यवस्था के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में, मुद्रास्फीति की गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। लगातार मुद्रास्फीति संबंधी दबाव नीति निर्माताओं और आम जनता के लिए कई चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं। वैश्विक स्तर पर, केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक सुधार के बीच संतुलन बनाने के लिए सावधानीपूर्वक अपनी प्रतिबंधात्मक नीतियों में ढील दे रहे हैं। भारत में, विभिन्न सरकारी पहल और मौद्रिक नीति समीक्षाएं मुद्रास्फीति दबाव को नियंत्रण में रखने में मदद कर रही हैं।

4.2 आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और भू-राजनीतिक तनावों के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति 2022 में 8.7 प्रतिशत के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो 2024[1] में 5.7 प्रतिशत हो गई। भारत में, चुनौतीपूर्ण खाद्य मूल्य गतिशीलता के बावजूद खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 5.4 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसम्बर) में 4.9 प्रतिशत हो गई है। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का लगभग दो/पांचवां हिस्सा है। इसलिए, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) खुदरा मुद्रास्फीति का महत्वपूर्ण निर्धारक है। हाल के वर्षों में, खाद्य मुद्रास्फीति, हेडलाइन मुद्रास्फीति में प्रमुख हिस्सेदार रही है। हालाँकि, कीमतों में वृद्धि सभी खाद्य श्रेणियों में व्यापक नहीं है। यह मुख्य रूप से कुछ वस्तुओं द्वारा संचालित होती है। इस प्रकार, इस अध्याय में उन प्रमुख खाद्य वस्तुओं का केंद्रित विश्लेषण दिया गया है जो खाद्य मुद्रास्फीति पर ऊपर की ओर दबाव डालते हैं।

4.3 इस संदर्भ को देखते हुए, इस अध्याय को चार खंडों में तैयार किया गया है। खंड 2 में वैश्विक मुद्रास्फीति का विश्लेषण किया गया है, जबकि खंड 3 के अंतर्गत घरेलू मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों की जांच की गई है और मुद्रास्फीति की गतिशीलता को प्रभावित करने वाले निकटतम कारकों पर चर्चा की गई है। इस अध्याय के खंड 4 की समाप्ति कुछ सिफारिशों के साथ होती है। इस प्रस्तुति योजना का उद्देश्य नीति निर्माताओं और हितधारकों को मुद्रास्फीति की गतिशीलता के बारे में एक सिंहावलोकन प्रदान करना है ताकि उन्हें मुद्रास्फीति के प्रबंधन की जटिलताओं का मार्ग निर्देशन करने में मदद मिल सके।

वैश्विक मुद्रास्फीति

समकालिक मौद्रिक नीति सख्ती के बीच वैश्विक लचीलापन

4.4 विभिन्न देशों में मौद्रिक नीति में तीव्र एवं समकालिक सख्ती के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने संपूर्ण अवमुद्रास्फीति प्रक्रिया के दौरान उत्पादन वृद्धि में लचीलेपन का असामान्य स्तर प्रदर्शित किया है। यह लचीलापन वित्त वर्ष 2024 और चालू वर्ष के दौरान अधिकांश देशों में हेडलाइन मुद्रास्फीति दर में लगातार गिरावट में परिलक्षित होता है। ब्याज दरों में वृद्धि और अन्य नीतिगत उपायों के माध्यम से मुद्रास्फीति को रोकने के लिए केंद्रीय बैंकों द्वारा किए गए ठोस प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति के दबावों में उल्लेखनीय कमी आई है।

1 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2025, जनवरी) वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक –: अपडेट–: ग्लोबल ग्रोथ: डाइवर्जेंट एंड अनसर्टेन वाशिंगटन, डीसी। (https://tinyurl.com/29ussy2x)

चार्ट IV.1(क): विभिन्न देशों में हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी

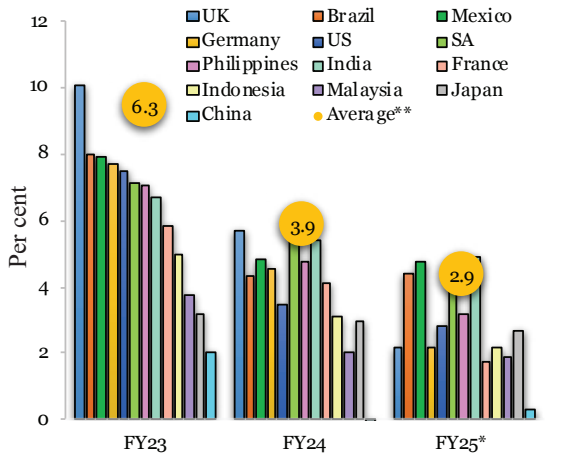

चार्ट IV.1(ख): मौद्रिक लक्ष्यीकरण ने वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति को कम किया और उत्पादन को स्थिर किया

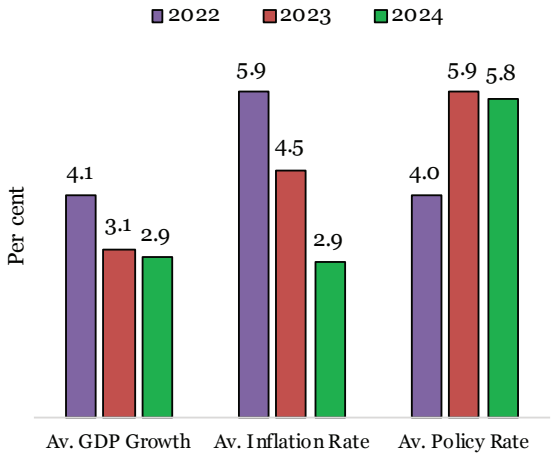

स्रोत: ब्लूमबर्ग और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आईएमएफ डब्ल्यूईओ डेटाबेस अक्टूबर 2024 और जनवरी 2025 तक अद्यतन, केंद्रीय बैंक नीति दरें, बीआईएस

नोट: *वित्त वर्ष 25 के लिए मुद्रास्फीति दर अप्रैल से दिसंबर 2024 तक है, जापान, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर नवंबर 2024 तक है। ** देशों का साधारण औसत चार्ट IV.1(क) में प्रस्तुत किया गया है।

कोर मुद्रास्फीति में गिरावट

4.5. हेडलाइन मुद्रास्फीति में गिरावट की प्रवृत्ति के अनुरूप, कोर मुद्रास्फीति, जिसमें अस्थिर खाद्य और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं हैं, भी अधिकांश देशों में कम हुई है। इस गिरावट का कारण मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय पण्य (कमोडिटी) कीमतों में नरमी को माना जा सकता है। यह प्रवृत्ति विभिन्न क्षेत्रों में कीमतों को स्थिर करने में नीतिगत हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है।

चार्ट IV.2: कोर मुद्रास्फीति भी कम हुई है

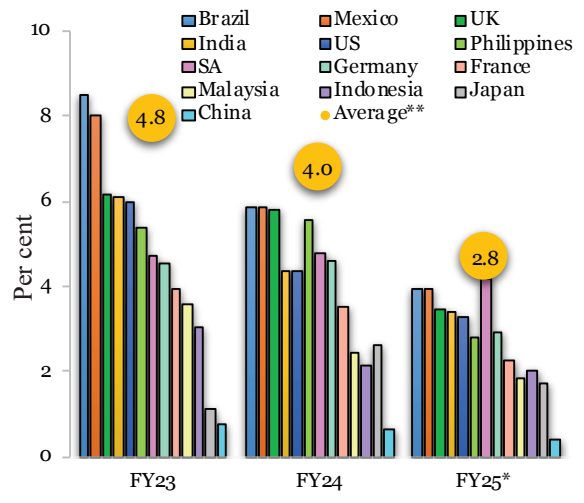

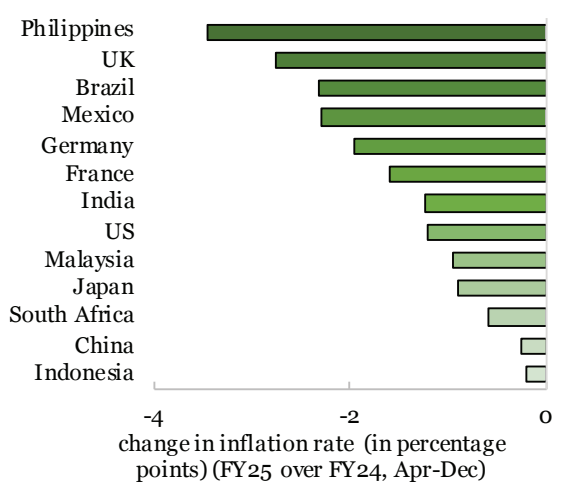

स्रोत: ब्लूमबर्ग और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

नोट: *वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति दर अप्रैल से दिसंबर 2024 तक है, जापान, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर नवंबर 2024 तक है। ** देशों का साधारण औसत चार्ट IV.2 में प्रस्तुत किया गया है।'

वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई है लेकिन कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भिन्नता बनी हुई है

4.6. वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट का रुख है, जो हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति दोनों में देखे गए पैटर्नों के अनुरूप है। अच्छी फसल और अनुकूल परिस्थितियों के कारण वैश्विक आपूर्ति स्थितियों में सुधार ने खाद्य कीमतों[2] में नरमी लाने में योगदान दिया है। हालाँकि, कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं, जैसे ब्राजील, भारत और चीन, में विपरीत पैटर्न है।

चार्ट IV.3 (क): वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट

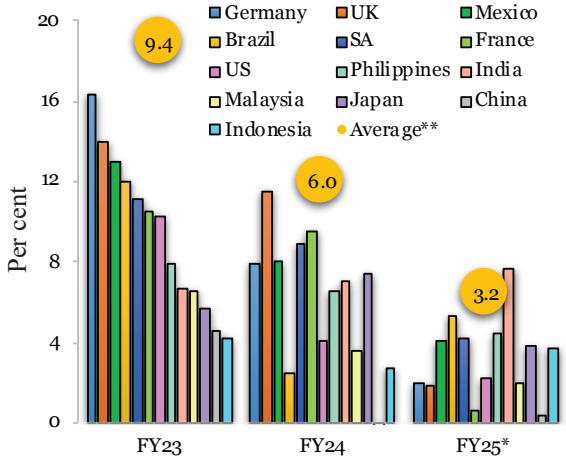

चार्ट IV.3 (ख): कुछ उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अलग-अलग प्रवृत्ति आलेख

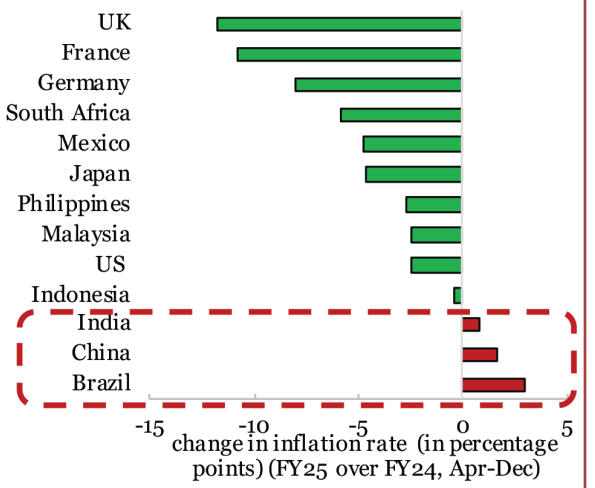

स्रोत: ब्लूमबर्ग और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
नोट: *वित्त वर्ष 2025 के लिए मुद्रास्फीति दर अप्रैल से दिसंबर 2024 तक है, जापान, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर नवंबर 2024 तक है। ** देशों का सरल औसत चार्ट IV.3(क) में प्रस्तुत किया गया है।

घरेलू मुद्रास्फीति

कोर मुद्रास्फीति में नरमी से हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी

4.7. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई भारत की हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 25 (अप्रैल-दिसम्बर) में वित्त वर्ष 2024 की तुलना में कम हुई है। यह गिरावट मुख्य रूप से कोर मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी के कारण हुई है, जो वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसम्बर) के बीच 0.9 प्रतिशत बिंदु कम हुई। कोर मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट मुख्यत: कोर सेवा मुद्रास्फीति के कारण हुई, जो कोर वस्तु मुद्रास्फीति की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम थी। ईंधन मूल्य मुद्रास्फीति में कमी ने भी हेडलाइन मुद्रास्फीति को कम करने में योगदान दिया है, जिससे घरेलू बजट पर दबाव कम हुआ है। सामान्य तौर पर, खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट को इनपुट की कीमतों में कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जैसा कि थोक मूल्य मुद्रास्फीति में परिलक्षित होता है, जो वित्त वर्ष 2024 में अपस्फीति जोन (-0.7 प्रतिशत) में थी और यह वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में कम रही।

2 कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, विश्व बैंक (2024, अक्टूबर) (https://tinyurl.com/dyduh9tu)-

चार्ट IV.4: हेडलाइन और कोर मुद्रास्फीति नियंत्रण में

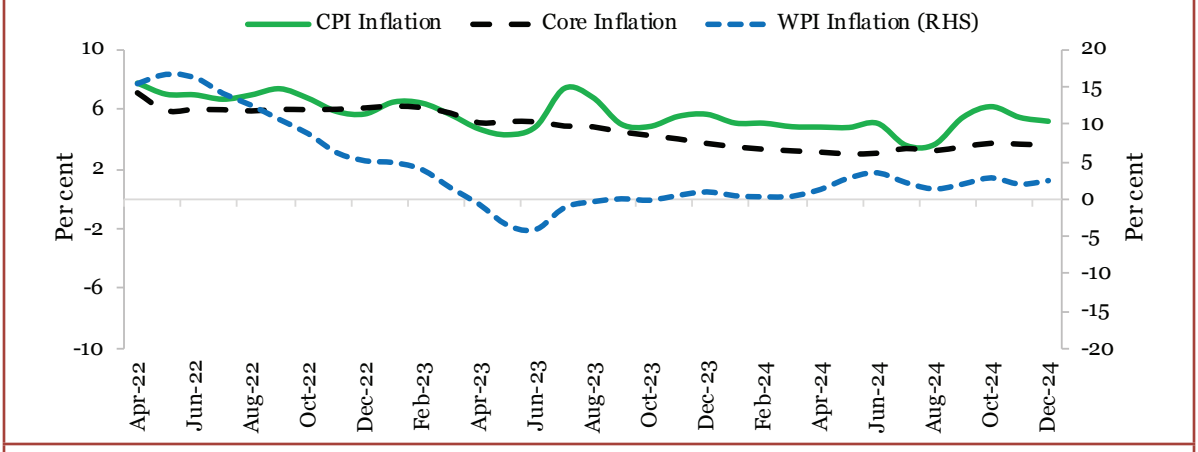

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

खाद्य मुद्रास्फीति मुख्य रूप से कुछ खाद्य वस्तुओं के कारण

4.8. पिछले दो वर्षों में भारत की खाद्य मुद्रास्फीति दर स्थिर बनी हुई है, जो स्थिर या घटती खाद्य मुद्रास्फीति के वैश्विक रुझानों से भिन्न हो रही है। इसका कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान जैसे कारक हो सकते हैं जो मौसम की चरम स्थितियों और कुछ खाद्य मदों की कम पैदावार के कारण और भी बदतर हो सकते हैं।

4.9. सीएफपीआई द्वारा आंकी गई खाद्य मुद्रास्फीति में वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल–दिसंबर) में वृद्धि देखी गई, जो मुख्य रूप से सब्जियों और दलहन जैसे कुछ खाद्य पदार्थों के कारण हुई। सीपीआई बास्केट में सब्जियों और दलहन का कुल वेटेज 8.42 प्रतिशत है। हालांकि, वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल से दिसंबर) में कुल मुद्रास्फीति में उनका योगदान 32.3 प्रतिशत रहा। जब इन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, तो वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल–दिसंबर) के लिए औसत खाद्य मुद्रास्फीति दर 4.3 प्रतिशत थी, जो समग्र खाद्य मुद्रास्फीति से 4.1 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार, सब्जियों और दलहन की मुद्रास्फीति दर को छोड़ देने पर औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति 3.2 प्रतिशत होगी, जो वास्तविक हेडलाइन मुद्रास्फीति से 1.7 प्रतिशत कम है।

चार्ट IV.5: सब्जियों और दलहन के कारण खाद्य मुद्रास्फीति

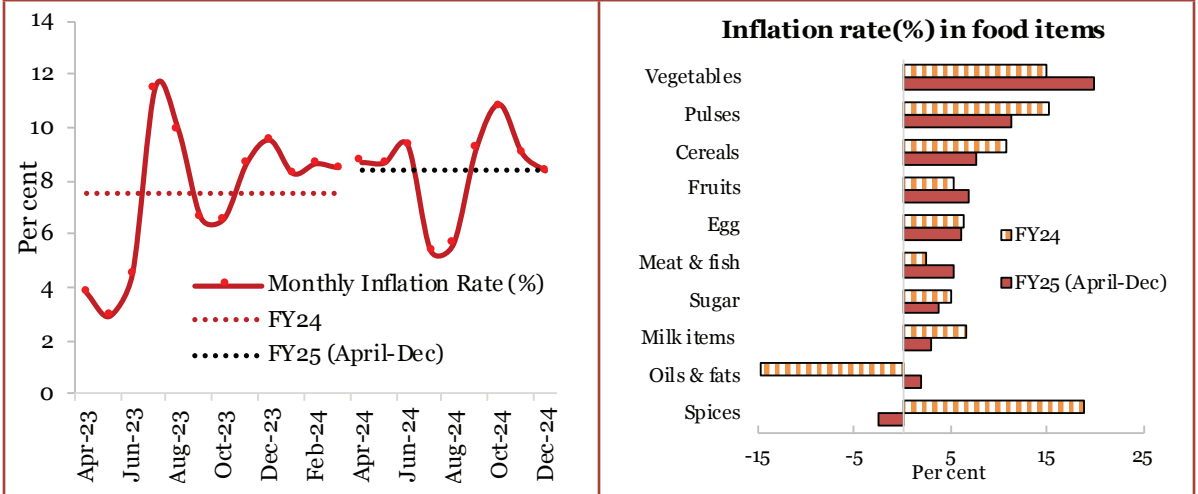

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

चार्ट IV.6 (क): टमाटर की खुदरा कीमतों में वृद्धि 2024 में उच्च अस्थिरता का संकेत देती है

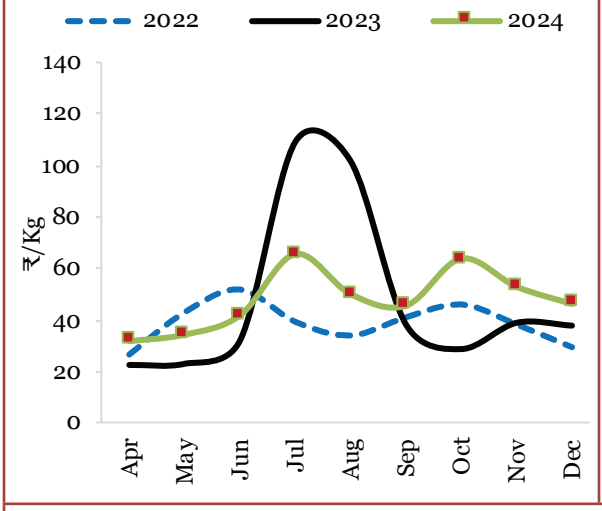

चार्ट IV.6 (ख): 2024 में प्याज की खुदरा कीमतें ऊंची बनी रहीं

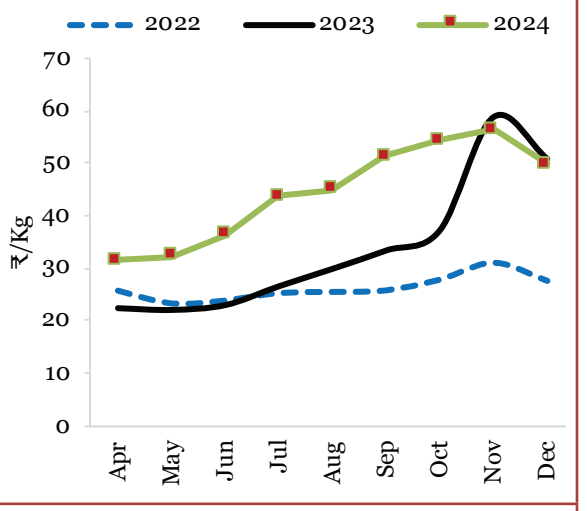

स्रोत: मूल्य निगरानी प्रभाग, उपभोक्ता मामले विभाग

4.10. असमान मानसून स्थितियों के कारण कुछ क्षेत्रों में आपूर्ति में व्यवधान होने से कीमतों में उछाल (प्राइस प्रेशर) आया, मुख्य रूप से टमाटर और प्याज में, जिससे सब्जियों की मुद्रास्फीति दर और समग्र खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। जब हम सीपीआई बास्केट से तीन सबसे अधिक मूल्य-संवेदनशील सब्जियों (टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी)) को बाहर करते हैं, तो वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में औसत खाद्य मुद्रास्फीति दर 6.5 प्रतिशत थी, जो वर्तमान खाद्य मुद्रास्फीति से 1.9 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार, टीओपी को छोड़कर औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत है, जो वर्तमान हेडलाइन मुद्रास्फीति से 0.7 प्रतिशत कम है। यह देखते हुए कि टमाटर और प्याज की कीमतें खाद्य मुद्रास्फीति का कारण रही हैं, और परिणामस्वरूप हाल के महीनों में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ी है, अगले खंड में इन सब्जियों पर मूल्य दबाव के कारणों का पता लगाया जाएगा।

चार्ट IV.7: हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति कुछ खाद्य वस्तुओं से प्रेरित

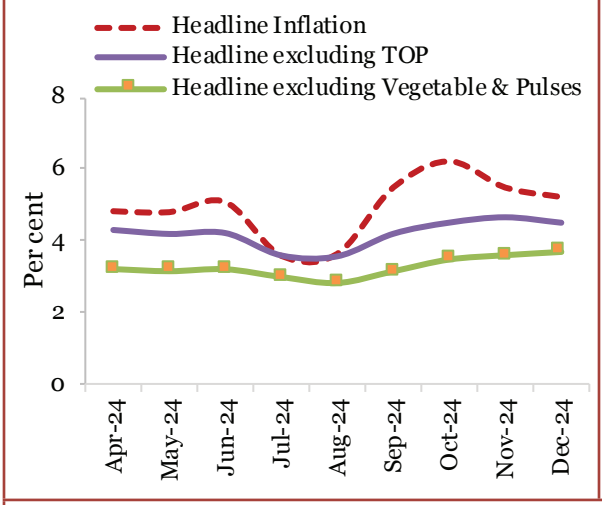

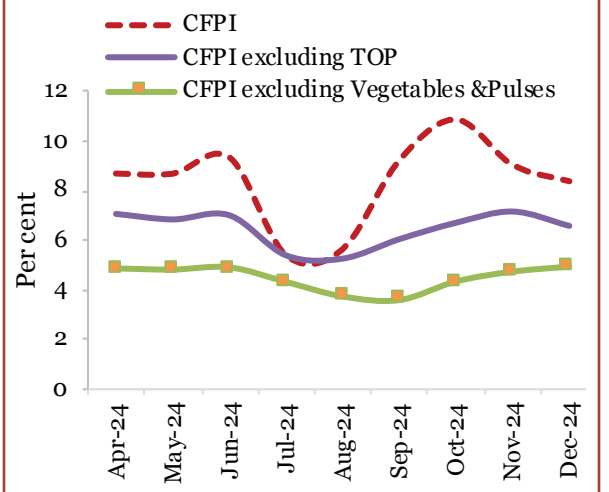

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

चरम मौसम स्थितियां सब्जी उत्पादन और कीमतों को प्रभावित करती हैं

4.11. विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट है कि खाद्यान्नों की तुलना में सब्जियों पर असमान मौसम का प्रभाव अधिक पड़ता है। चक्रवात, भारी वर्षा, बाढ़, आंधी, ओलावृष्टि और सूखे जैसी चरम मौसम संबंधी घटनाएं सब्जियों की कीमतों को प्रभावित करती हैं। इसके अतिरिक्त, साक्ष्य बताते हैं कि 2023-24 में बागवानी वस्तुओं में मुद्रास्फीति के दबाव का कारण मानसून-पूर्व मौसम के दौरान बेमौसम बारिश का होना था, जिसने प्रमुख बागवानी उत्पादक राज्यों में फसलों को नुकसान पहुंचाया।[3] बड़े क्षेत्र में बुआई के साथ-साथ कीमतों में अधिक अस्थिरता से पता चलता है कि चरम मौसम की घटनाएं उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, जिससे खुदरा कीमतें प्रभावित होती हैं।

4.12. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि चरम मौसम की स्थिति, विशेष रूप से हीटवेव की आवृत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। औसतन, 2022-2024 के दौरान, भारत ने 2020 और 2021 में 5 प्रतिशत दिनों की तुलना में 18 प्रतिशत दिनों में हीटवेव का अनुभव किया।

चार्ट IV.8: पिछले 3 वर्षों मे हीटवेव में वृद्धि हुई

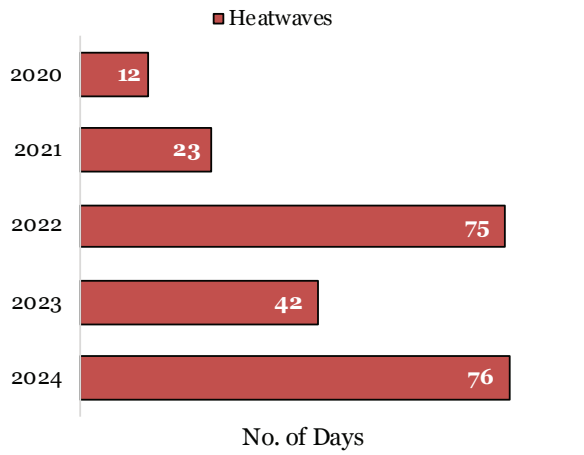

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

चार्ट IV.9: मौसम की स्थिति के कारण क्षतिग्रस्त फसल क्षेत्र

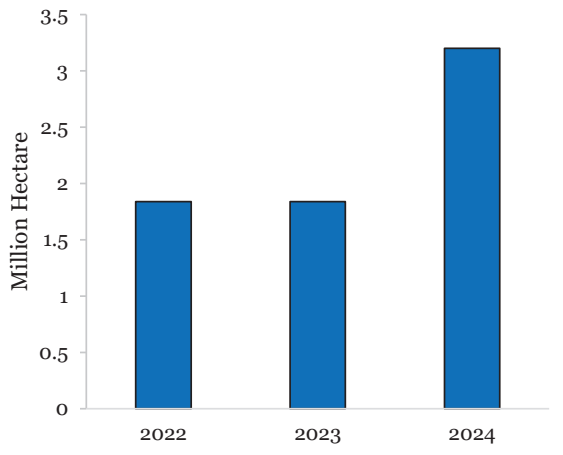

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट डाउन टू अर्थ द्वारा भारत के मौसम आपदा डैशबोर्ड का डेटाबेस।[4]

4.13. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) और डाउन टू अर्थ (डीटीई)[5,6] द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 में चरम मौसम की घटनाओं के कारण क्षतिग्रस्त कुल फसल क्षेत्र पिछले दो वर्षों की तुलना में अधिक था।

3 राया, डी. और रॉय, आर. (2023). बागवानी फसलों में बेमौसम बारिश और मूल्य वृद्धि। क्लाइमेट-रूफिंग एग्रीकल्चर. एग्री-फूड ट्रेंड्स एंड एनालिटिक्स बुलेटिन वोल 3. इश्यू-1. (https://tinyurl.com/yyr8fzek)

4 आंकड़े केंद्रीय गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग, भारतीय मौसम विभाग और मीडिया रिपोर्टों से प्राप्त हुए हैं

5 विज्ञान और पर्यावरण केंद्र और डाउन टू अर्थ (2024)। क्लाइमेट इंडिया 2024: एन असेसमेंट ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स. नवंबर. https://tinyurl.com/2r5r85dw.

6 सीएसई/डीटीई आईएमडी वेबसाइट से प्रत्येक दिन की रिपोर्ट ट्रैक करता है और राज्य व संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में और घटना के प्रकार के अनुसार घटनाओं का मानचित्रण करता है।

4.14. चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति – विशेष रूप से असमान और बेमौसम वर्षा, और हीटवेव सब्जी उत्पादन को प्रभावित करती हैं, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। ये प्रतिकूल मौसम स्थितियां भंडारण और परिवहन के लिए भी महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपूर्ति श्रृंखला में अस्थायी व्यवधान उत्पन्न होता है और सब्जियों की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इस घटना की पुष्टि किसी प्रदत्त महीने में होने वाली चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और बाद के महीनों में देखी गई सब्जी मुद्रास्फीति दरों के बीच सकारात्मक सहसंबंध से भी होती है, और ऐसी घटनाओं के बाद तीन महीने तक उल्लेखनीय प्रभाव स्पष्ट दिखाई देते हैं।

चार्ट IV.10: अप्रैल-2020 से दिसम्बर-2024 में परवर्ती महीनों में मुद्रास्फीति को बढ़ाने वाली चरम मौसम की घटनाओं की उच्चतर आवृत्ति

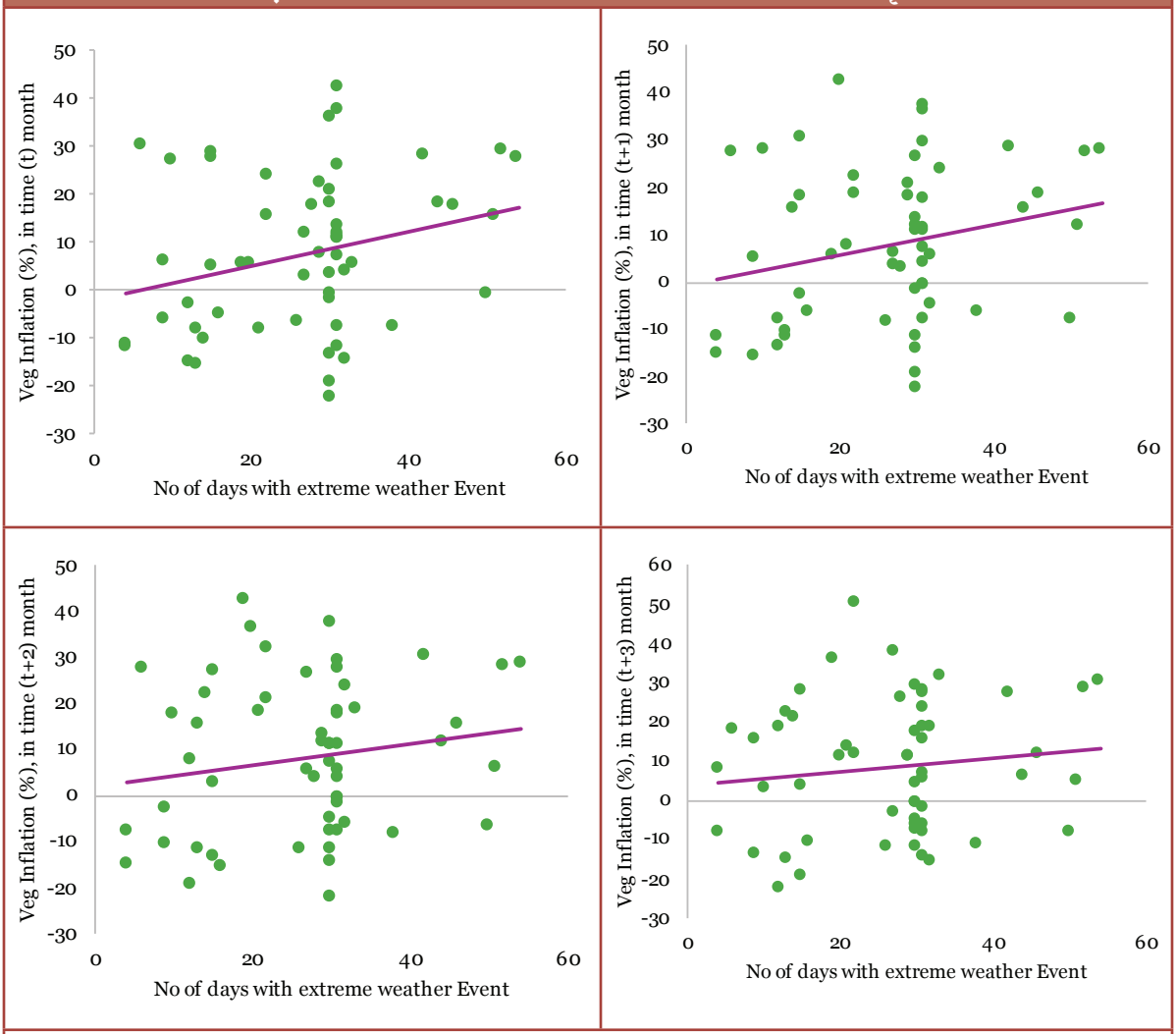

स्रोत: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
नोट: चरम मौसम की घटनाओं वाले दिनों की संख्या (चार्ट IV.17 में क्षैतिज अक्ष) = भारी वर्षा वाले दिनों की संख्या + हीटवेव वाले दिनों की संख्या

4.15. इसके अलावा, पिछले दो वर्षों में प्याज और टमाटर के उत्पादन में गिरावट को आंशिक रूप से अन्य क्षेत्रों की तुलना में प्रमुख उत्पादक राज्यों में अधिक चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव से समझाया जा सकता है।

चार्ट IV.11: प्रमुख टमाटर और प्याज उत्पादक राज्यों में 2024 में अधिक हीटवेव का अनुभव हुआ

2020 में हीटवेव वाले दिनों की संख्या	2024 में हीटवेव वाले दिनों की संख्या

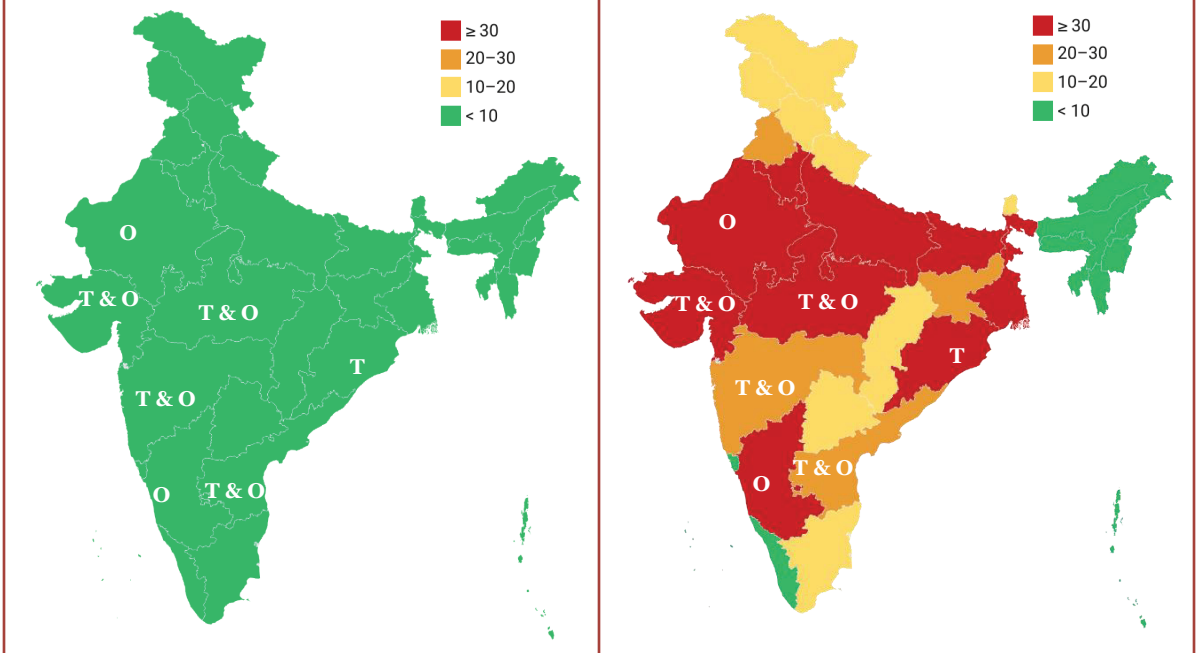

स्रोत: .आईएमडी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
नोट: T प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्य को दर्शाता है और O प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य को दर्शाता है
(ii) राज्य-वार हीटवेव डेटा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए संबंधित सब डिवीजन को शामिल किया गया है।

प्याज और टमाटर के उत्पादन और कीमतों की प्रवृत्ति

4.16. कम उत्पादन के परिणामस्वरूप सीमित आपूर्ति के कारण कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा त्वरित उपाय किए जाने के बावजूद, वित्त वर्ष 2024 और चालू वर्ष में प्याज में मुद्रास्फीति का दबाव मजबूत बना रहा। प्याज खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाया जाता है, और लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन रबी मौसम के दौरान होता है[7]। ताजे प्याज आमतौर पर ठंडी, सूखी और हवादार जगह में 2-3 महीने तक चलते हैं, और नमी रहित वातावरण में इनका भंडारण व उपयोग होने तक की अवधि (शेल्फ लाइफ) और भी बढ़ सकती है। इस प्रकार, एक वर्ष में उत्पादित प्याज - विशेष रूप से मार्च से काटे गए रबी प्याज आमतौर पर अगले वर्ष खपत के लिए उपलब्ध होते हैं, जिससे उस वर्ष मुद्रास्फीति उतार-चढ़ाव प्रभावित होता है। 2022-23 और 2023-24 में कम उत्पादन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) में प्याज में स्फीतिकारक दबाव बढ़ा है (चार्ट IV.6ख)।

7 उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (2024, 5 जुलाई)। खरीफ मौसम में प्याज की बुआई का क्षेत्रफल पिछले साल से 27% अधिक रहने का अनुमान; कर्नाटक में 30% बुआई पूरी हो चुकी है [पीआईबी विज्ञप्ति]। (https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2031043-reg=3-lang=1)

चार्ट IV-12: विभिन्न क्षेत्रों में प्याज उत्पादन की प्रवृत्ति

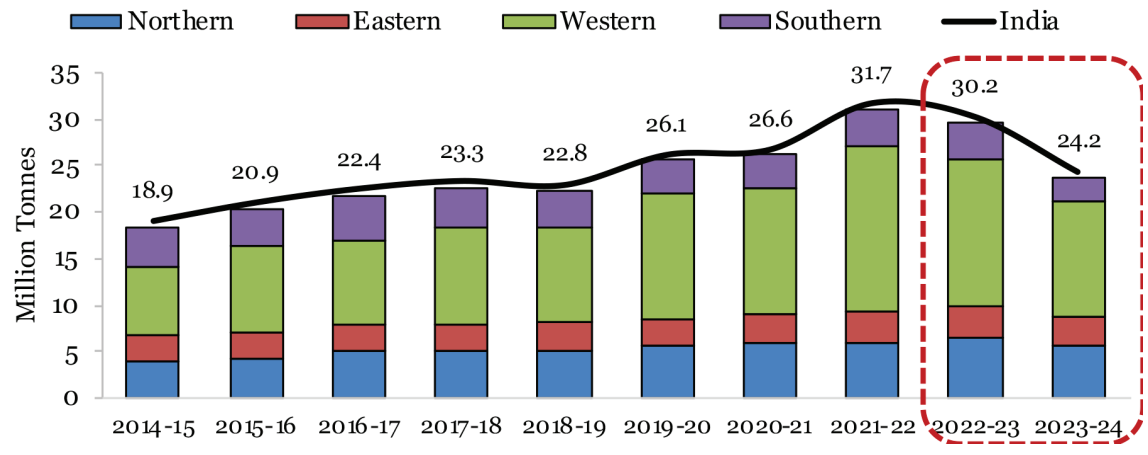

स्रोत: बागवानी सांख्यिकी इकाई, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

4.17. सीमित आपूर्ति के कारण वित्त वर्ष 2023 से टमाटर की कीमत में रुक-रुक कर उतार-चढ़ाव जारी है (चार्ट IV-6क)। ऐसा तब हुआ जब सरकार ने उत्पादक क्षेत्रों से खरीद करके कमी वाले क्षेत्रों में आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाने के लिए गंभीर प्रयास किए। टमाटर की मुद्रास्फीति की गतिशीलता कई कारकों से प्रभावित होती है। प्याज के विपरीत, टमाटर का फसल चक्र छोटा होता है और यह बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जिससे भंडारण और परिवहन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं तथा आपूर्ति में कमी आती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। ताजे टमाटरों को अगर सही तरीके से भंडारित किया जाए तो वे सिर्फ 1-2 हफ्ते तक ही टिक पाते हैं। टमाटर का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और ओडिशा जैसे राज्यों में संकेंद्रित रहता है। यह क्षेत्रीय संकेन्द्रण आपूर्ति श्रृंखला को इनमें से किसी भी क्षेत्र में व्यवधान के प्रति संवेदनशील बनाता है। प्याज की तरह, टमाटर उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा - 65 प्रतिशत[8] से अधिक - रबी मौसम में होता है।

चार्ट IV-13: विभिन्न क्षेत्रों में टमाटर उत्पादन की प्रवृत्ति

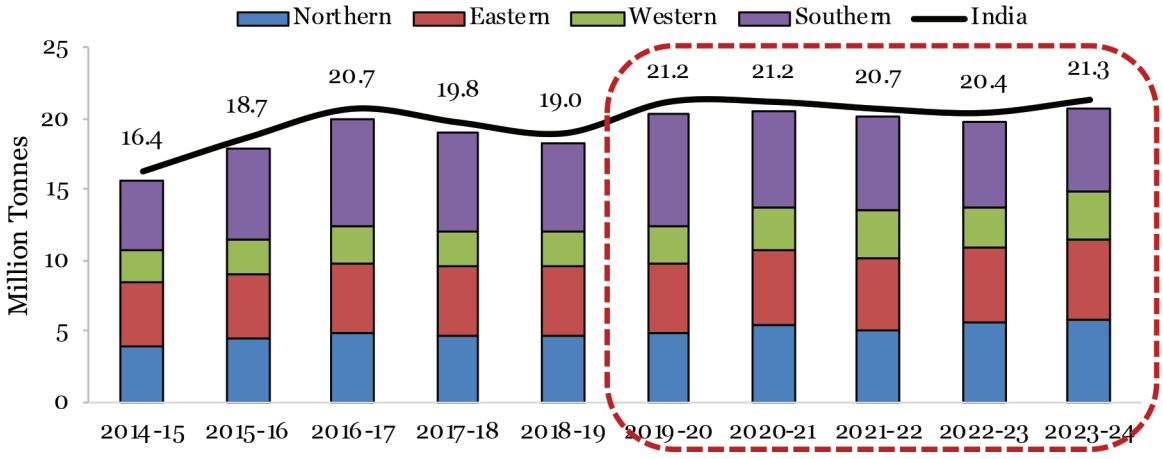

स्रोत: बागवानी सांख्यिकी इकाई, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी एवं मूल्यांकन प्रभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

8 रॉय, आर., और अन्य (2024)। वेजिटेबल्स इन्फ्लेशन इन इंडिया: ए स्टडी ऑफ टोमेटो, ओनियन एंड पोटाटो (टीओपी). आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई वर्किंग पेपर सीरीज संख्या 08.(https://www.rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspxx?id=22723)

प्याज और टमाटर का मौसमी उत्पादन और खपत

4.18. पिछले तीन वर्षों के उत्पादन और खपत प्रवृत्ति के विश्लेषण से पता चलता है कि टमाटर और प्याज दोनों की घरेलू खपत, उत्पादन से कम है। बागवानी सांख्यिकी एक नजर 2021[9] से सूचना मिलती है कि लगभग 15 प्रतिशत उत्पादन का उपयोग होटलों, शादियों आदि में थोक खपत के रूप में किया जाता है। इसे घरेलू उपभोग के अतिरिक्त उपभोग के रूप में देखने पर भी उत्पादन अभी भी अधिक है। इसलिए, यह पता चलता है कि मूल्य में उतार-चढ़ाव मूलतः उत्पादन में कमी के कारण नहीं है, बल्कि कटाई के बाद होने वाले नुकसान, मौसमी उत्पादन और उत्पादन में क्षेत्रीय वितरण के कारण है। साथ ही, वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2024 के दौरान प्याज के घरेलू उत्पादन का निर्यात औसतन 6 प्रतिशत से अधिक रहा है।

चार्ट IV-14: घरेलू खपत उत्पादन से कम है

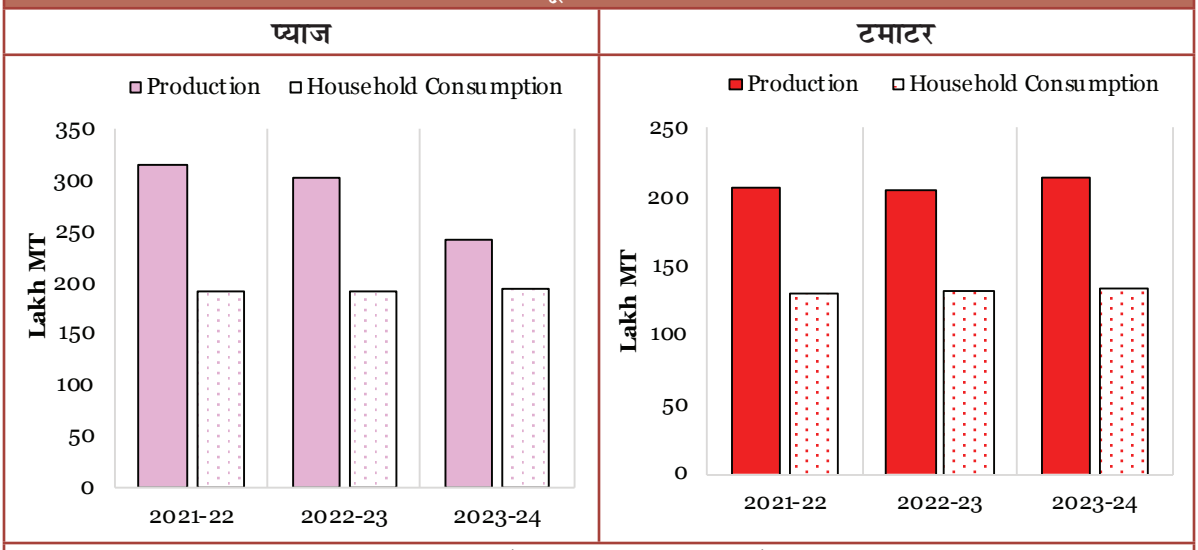

स्रोत: बागवानी सांख्यिकी इकाई, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी और मूल्यांकन प्रभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, 2022-23, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011 - 2036, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नोट: वार्षिक घरेलू उपभोग की गणना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, 2022-23 की रिपोर्ट से की जाती है।

4.19. उदाहरण के लिए, टमाटर की कीमतें आमतौर पर जुलाई से सितंबर तक बढ़ जाती हैं, यह कम उत्पादन का मौसम है जो मानसून के साथ मेल खाता है, जिससे वितरण से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं और परिवहन के दौरान क्षति बढ़ जाती है। प्याज की कीमतें अक्टूबर से दिसंबर तक बढ़ जाती हैं, जो प्याज उत्पादन के लिए कम उत्पादन का मौसम दर्शाता है। प्याज और टमाटर के प्रमुख उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में भारत की स्थिति मौसमी आपूर्ति और मांग असंतुलन के समय में आयात की संभावना को काफी हद तक सीमित कर देती है। यह देखते हुए कि भारत और चीन प्याज के कुल उत्पादन में आधे के करीब का योगदान करते हैं[10], मांग-आपूर्ति असंतुलन की अवधि के दौरान भारत के लिए आयात विकल्प काफी सीमित हैं। अगले आठ प्रमुख उत्पादक देश, उत्पादन में केवल 18 प्रतिशत का योगदान देते हैं। साथ ही, टमाटर की जल्दी खराब होने वाली प्रकृति पड़ोसी देशों से आयात विकल्पों को सीमित करती है, जो टमाटर के बड़े उत्पादक नहीं हैं। नतीजतन, भारत को इन आवश्यक वस्तुओं के आयात में समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

9 बागवानी सांख्यिकी एक नजर में, 2021, बागवानी सांख्यिकी प्रभाग कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (https://agriwelfare.gov.in/Documents/Horticultural_Statistics_at__Glance_2021.pdf)

10 संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन। (2023)। FAOSTAT lkaf[;dh; MsVkcslA jkse% FAO

तालिका IV.1: प्याज और टमाटर का फसल-कैलेंडर				
सब्जी	**उत्पादन में हिस्सा**	**मौसम**	**प्रत्यारोपण**	**कटाई अवधि**
प्याज	30%	खरीफ	जुलाई - अगस्त	अक्टूबर-दिसंबर
		खरीफ	अक्टूबर-नवंबर	जनवरी - मार्च
	70%	**रबी**	**दिसंबर - जनवरी**	**मार्च के अंत से मई तक**
टमाटर	33%	खरीफ	मई-जुलाई	जुलाई-सितंबर
	67%	**रबी**	**अक्टूबर-नवंबर जनवरी-फरवरी**	**दिसंबर-जून**
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो विज्ञप्ति, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय[11]				

तुअर (अरहर) के उत्पादन और मुद्रास्फीति दर की प्रवृत्ति

4.20. टमाटर और प्याज के अतिरिक्त, अरहर दाल ने भी भारत में खाद्य मुद्रास्फीति में योगदान दिया है। वर्ष 2022-23 और 2023-24 में अरहर के कम उत्पादन के कारण वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान अरहर दाल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, जबकि सरकार ने उपभोक्ता क्षेत्रों में आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई उपाय किए। पिछले 5 वर्षों के औसत की तुलना में 2022-23 में उत्पादन में 13.6 प्रतिशत तथा 2023-24 में 10.8 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे आपूर्ति प्रभावित हुई है। पिछले दशक में, वार्षिक मुद्रास्फीति दर और 1 वर्ष के विलंबित उत्पादन के बीच एक मजबूत नकारात्मक सहसंबंध (-0.8) रहा है, जो आमतौर पर दर्शाता है कि एक वर्ष में कम उत्पादन का परिणाम अगले वर्ष में उच्च मुद्रास्फीति होता है। प्रमुख खरीफ दाल के रूप में, अरहर की कटाई नवंबर से जनवरी तक की जाती है, जिसका मूल्य प्रभाव मुख्य रूप से अगले वित्त वर्ष में देखा जाता है।

चार्ट IV.15: तुअर उत्पादन और मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति

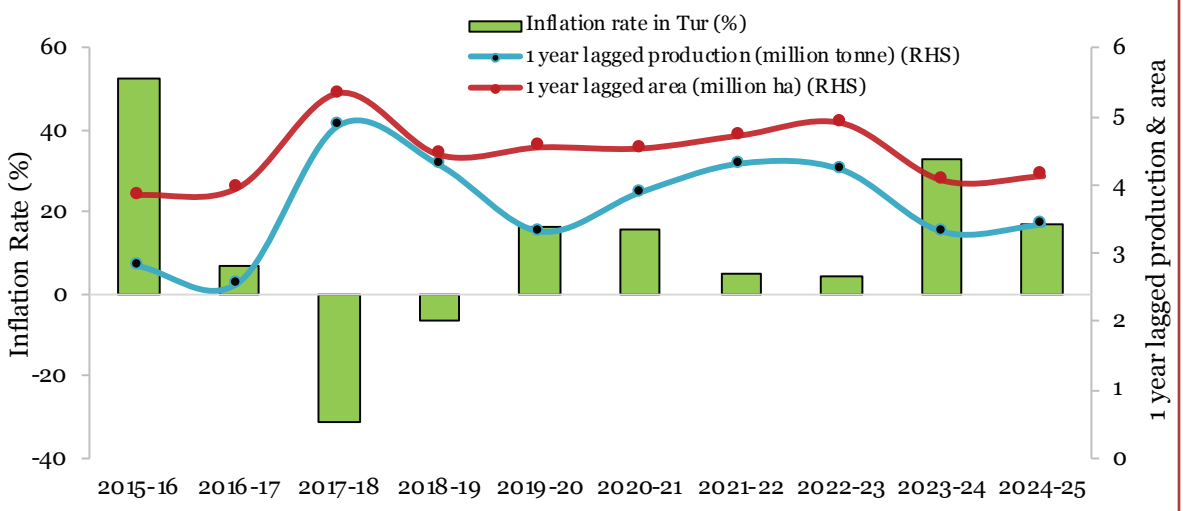

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

11 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2074016A https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2031043-reg=3-lang=1

4.21. इन चुनौतियों के बावजूद, सरकार उपभोक्ताओं को तुअर दाल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्पादित मात्रा बाजार तक पहुंचे और संचयन भंडारण को रोकने के लिए, सरकार समय-समय पर तुअर के लिए स्टॉक सीमा लगाकर और स्टॉक प्रकटीकरण पोर्टल के माध्यम से सक्रिय निगरानी करके सतर्क कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त, तुअर की मांग को पूरा करने के लिए, देश ने वित्त वर्ष 2024 में 7.7 लाख टन तुअर का आयात मुख्य रूप से मोजाम्बिक, तंजानिया, मलावी और म्यांमार से किया गया।

बॉक्स IV.1: खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक कदम

खाद्य वस्तुएं	लिए गए कदम
अनाज	• 24 जून 2024 से 31 मार्च 2025 तक गेहूं पर स्टॉक सीमा लागू की गई। • खुले बाजार की बिक्री योजना: केंद्रीय पूल से गेहूं और चावल दिया गया • भारत ब्रांड के अन्तर्गत गेहूं के आटे और चावल की बिक्री।
दालें	• भारत ब्रांड के अन्तर्गत चना दाल, मूंग दाल और मसूर दाल की बिक्री • 21 जून 2024 से 30 सितंबर 2024 तक तुअर और देसी चना पर स्टॉक सीमा लगाई गई। • 31 मार्च 2025 तक देसी चना, तुअर, उड़द और मसूर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई। • 20 फरवरी 2025 तक पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई।
सब्जियां	• प्याज का बफर स्टॉक: मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत कुल 4.7 लाख मीट्रिक टन रबी प्यांज की खरीद की गई है। • 13 सितम्बर 2024 से प्याज पर 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क। • सितंबर-दिसंबर 2024 तक 35 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज की रियायती दर पर बिक्री। • अक्टूबर 2024 में 65 रुपये प्रति किलोग्राम टमाटर की रियायती दर पर बिक्री।
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो की विभिन्न विज्ञप्तियाँ	

दृष्टिकोण और भविष्य की दिशा

4.22. भारतीय रिजर्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया है कि भारत की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति लक्ष्य की ओर धीरे-धीरे बढ़ेगी। दिसंबर 2024 की भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2025 में मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया गया है। सामान्य मानसून और आगे कोई बाहरी या नीतिगत झटके न आने के अनुमान से भारतीय रिजर्व बैंक को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2026 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए वित्त वर्ष 2025 में 4.4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2026 में 4.1 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया है।

4.23 विश्व बैंक के कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक[12], अक्टूबर 2024 के अनुसार, पण्य वस्तुओं (कमोडिटी) की कीमतों में 2025 में 5.1 प्रतिशत और 2026 में 1.7 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। अनुमानित गिरावट तेल की कीमतों के कारण है, लेकिन प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि और धातुओं तथा कृषि से संबंधित कच्चे माल की स्थिर कीमतों से यह कम हो जाएगी। बहुमूल्य धातुओं में, सोने की कीमतों में कमी आने की उम्मीद है, जबकि चांदी की कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है। धातुओं और खनिजों की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है, मुख्य रूप से लौह अयस्क और जस्ता की कीमतों में कमी के कारण। सामान्य तौर पर, भारत द्वारा आयातित वस्तुओं की कीमतों में अधोमुखी प्रवृत्ति संचलन घरेलू मुद्रास्फीति संभावना के लिए सकारात्मक है।

चार्ट IV.16: अगले दो वर्षों में पण्य वस्तुओं (कमोडिटी) की कीमतों में नरमी आएगी

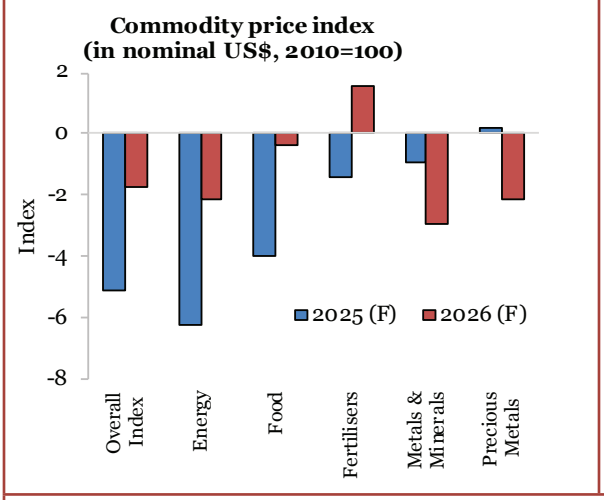

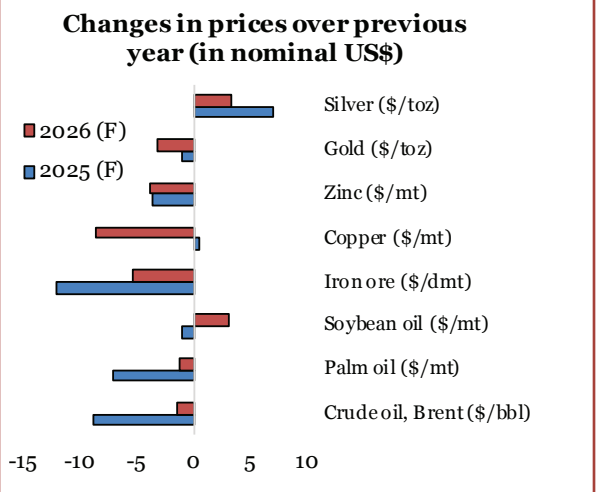

स्रोत: विश्व बैंक कमोडिटी मार्केट आउटलुक, अक्टूबर 2024

4.24 2024 में सामान्य दक्षिण-पश्चिम मानसून के कारण जलाशयों के जल स्तर में सुधार हुआ है, जिससे रबी फसल उत्पादन के दौरान सिंचाई के लिए पर्याप्त जल सुनिश्चित हुआ है। 2024-25 के लिए कृषि उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, खरीफ खाद्यान्न उत्पादन में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। खरीफ के सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न चावल और तुअर का उत्पादन 2023-24 की तुलना में क्रमशः 5.9 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। इससे वर्ष के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव में नरमी आ सकती है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय वनस्पति तेल की बढ़ती कीमतें खाद्य मुद्रास्फीति के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं। सरकार ने विभिन्न आपूर्ति उपायों के माध्यम से खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें आवश्यक खाद्य वस्तुओं के बफर स्टॉक को मजबूत करना और समय-समय पर खुले बाजार में जारी करना, निर्दिष्ट दुकानों में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की सब्सिडी वाली खुदरा बिक्री, शुल्कों को युक्तिसंगत बनाने के माध्यम से आवश्यक खाद्य वस्तुओं के आयात को आसान बनाना, स्टॉक सीमा लगाने/संशोधन और निगरानी के माध्यम से जमाखोरी की रोकथाम शामिल है। बजट 2024-25 में सब्जी उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर क्लस्टर बनाने, सब्जी आपूर्ति श्रृंखला के लिए किसान विकास -उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों और स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने तथा दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उपायों की परिकल्पना की गई है।

12 कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, विश्व बैंक (2024, अक्टूबर) (https://tinyurl.com/dyduh9tu).

4.25 कीमतों की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करना उचित हो सकता है–

- भारत को दलहन और तिलहनों के उत्पादन में लगातार कमी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही टमाटर और प्याज के उत्पादन में लगातार उतार–चढ़ाव के कारण कीमतों में वृद्धि हो रही है। इस समस्या से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील फसल की किस्मों को विकसित करने, उपज बढ़ाने और फसल क्षति को कम करने के लिए लक्षित अनुसंधान की आवश्यकता है। चावल की परती भूमि वाले क्षेत्रों में दलहन की खेती के क्षेत्र का विस्तार करने के प्रयासों से मदद मिलने की संभावना है।
- विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। किसानों को सर्वोत्तम पद्धतियों, उच्च उपज और रोग प्रतिरोधी बीज किस्मों के उपयोग और दलहन, टमाटर और प्याज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने के लिए लक्षित अंत:क्षेपों पर प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।
- सरकार के विभिन्न स्तरों पर कीमतों, स्टॉक और भंडारण और संसाधन सुविधाओं की निगरानी के लिए मजबूत डेटा संग्रह और विश्लेषण प्रणाली को लागू करना आवश्यक है। इस डेटा का उपयोग सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने और सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए किया जाना चाहिए। देश के भीतर विभिन्न एजेंसियों द्वारा एकत्रित आवश्यक खाद्य वस्तुओं के लिए उच्च–आवृत्ति कीमत निगरानी डेटा खेत से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक प्रत्येक चरण में कीमतों में होने वाली उतरोत्तर वृद्धि को आंकने और निगरानी करने के लिए संयोजित किया जा सकता है।

******

यह पृष्ठ खाली छोड़ दिया गया है।